



Neutral Citation No. - 2026:AHC:59046-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 413 के अंतर्गत आपराधिक अपील (दोषपूर्ण) संख्या - 50/2026

सोनूअपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्यप्रत्यर्थी

अपीलार्थी के अधिवक्ता: आनंद पति तिवारी

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 43

माननीय न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय,

माननीय न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-I,

(दाण्डिक प्रकीर्ण विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र संख्या 01/2026 पर आदेश)

बी.एन.एस.एस. की धारा 413 के अंतर्गत वर्तमान अपील अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. 2, औरैया द्वारा सत्र विचारण संख्या 149/2014 (मुकदमा अपराध संख्या 277/2013, धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता, थाना दिबियापुर, जनपद औरैया से उत्पन्न) में पारित दोषमुक्ति आदेश दिनांक 09.12.2025 को चुनौती देते हुए दायर की गई है।

अपील समय सीमा से 7 दिन की देरी से दायर की गई है।

विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दायर शपथ पत्र में विलम्ब का संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया गया है।

विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपील दायर करने में हुए विलम्ब को एतद्वारा क्षमा किया जाता है।

कार्यालय अपील को नियमित संख्या आवंटित करे।

अपील पर आदेश

अभियोजन का मामला, संक्षेप में, यह है कि अभियुक्त मल्लिका (मृतक) का किराएदार था और मृतक से पैसे और गहनों की मांग कर रहा था। जब मृतक ने अभियुक्त की मांगों को स्वीकार नहीं किया, तो अभियुक्त ने उसे जहर देकर मार डाला। घटना 18.08.2013 को हुई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक के बेटे द्वारा 27.09.2013 को दर्ज कराई गई थी। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त द्वारा मृतक को जहर दिए जाने का उल्लेख नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया है कि

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अभियुक्त, कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ, मृतक को जबरन कहीं ले जा रहा था, जिस कृत्य को नरेश चंद्र और हुकुम सिंह यादव तथा अन्य व्यक्तियों ने देखा था।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद, पंचायतनामा तैयार किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक के शव का पोस्टमार्टम 19.08.2013 को किया गया और विसरा सुरक्षित रखा गया। विसरा रिपोर्ट 21.02.2014 को प्राप्त हुई जिसमें यह खुलासा हुआ कि मृतक ने एल्युमीनियम फॉस्फेट का सेवन किया था।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर, अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया और मामले को विचारण के लिए सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। सत्र न्यायालय ने अभियुक्त पर धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप तय किए। अभियुक्त ने आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग की।

अभियोजन पक्ष ने अपना मामला सिद्ध करने के लिए ग्यारह गवाहों का परीक्षण किया।

प्रथम सूचनाकर्ता, जो मृतक का बेटा है, का पीडब्ल्यू-1 के रूप में परीक्षण किया गया। मृतक की बेटी का पीडब्ल्यू-3 के रूप में और एक दूर की रिश्तेदार, ममता देवी का पीडब्ल्यू-2 के रूप में परीक्षण किया गया। मृतक की भाभी का पीडब्ल्यू-5 के रूप में परीक्षण किया गया। एक संजय, जो अभियुक्त द्वारा मृतक को अपने वाहन में ले जाने का चश्मदीद गवाह होने का दावा करता है, का पीडब्ल्यू-4 के रूप में परीक्षण किया गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का पीडब्ल्यू-6 के रूप में परीक्षण किया गया। विभिन्न विवेचकों का पीडब्ल्यू-7, पीडब्ल्यू-8, पीडब्ल्यू-9 और पीडब्ल्यू-11 के रूप में परीक्षण किया गया। हेड कांस्टेबल, जो पंचायतनामा का गवाह है, का पीडब्ल्यू-10 के रूप में परीक्षण किया गया।

अभियोजन का यह स्वीकृत मामला है कि पीडब्ल्यू-1, जो मृतक का बेटा और प्रथम सूचनाकर्ता है, और पीडब्ल्यू-3, जो मृतक की बेटी है, घटना की तिथि को मुंबई में थे।

अपनी गवाही में, पीडब्ल्यू-1 ने कहा कि उसे अपनी मां की मृत्यु के बारे में उसके मामा पतिराम ने 18.08.2013 को ही फोन पर सूचित किया था। पीडब्ल्यू-1 ने कहा कि पतिराम ने गवाह को बताया था कि अभियुक्त ने मृतक को जहर देकर मार डाला है। गवाह और पीडब्ल्यू-3 दिनांक 19.08.2013 को औरैया, यानी अपराध स्थल पर पहुंचे और मृतक के पड़ोसियों हुकुम सिंह और नरेश चंद्र शुक्ला ने उन्हें बताया कि अभियुक्त ने घटना से दो-तीन दिन पहले मृतक के साथ मारपीट की थी। अस्पताल लाए जाने पर डॉक्टरों ने मृतक को मृत घोषित कर दिया था।

पीडब्ल्यू-2, जो खुद को मृतक की दूर की रिश्तेदार बताती है, ने अपनी गवाही में कहा कि 18.08.2013 को वह मृतक से उसके घर मिलने गई थी जहां गवाह ने देखा कि अभियुक्त और कुछ अन्य व्यक्ति मृतक को जबरन वह पिला रहे थे जिसे वे डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा कह रहे थे। गवाह द्वारा यह कहा गया है कि गीता, जो मृतक की रिश्तेदार भी है, उक्त तिथि को गवाह के साथ थी और उक्त घटना की गवाह भी थी। गवाह द्वारा आगे यह कहा गया है कि उसने 18.08.2013 को ही विवेचक को एक शपथ पत्र दिया था जिसमें कहा गया था कि अभियुक्त ने मृतक को जहर दिया था। अपनी जिरह में, गवाह ने कहा कि शपथ पत्र एक अधिवक्ता द्वारा तैयार किया गया था। गवाह द्वारा आगे यह कहा गया है कि उसने प्रथम सूचनाकर्ता और मृतक की बेटी को उक्त घटना का खुलासा नहीं किया था।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पीडब्ल्यू-3, जो मृतक की बेटाई है, ने अपनी गवाही में कहा कि अभियुक्त ने मृतक को उसके स्वामित्व वाले एक प्लॉट को बेचने के लिए मजबूर किया था और वह मृतक से लगातार पैसे और गहनों की मांग कर रहा था। गवाह द्वारा यह कहा गया है कि उक्त तथ्य का खुलासा मृतक ने उसे किया था। अपनी गवाही में, गवाह ने यह भी कहा कि नरेश चंद्र और हुकुम सिंह ने गवाह को सूचित किया था कि अभियुक्त ने घटना से दो-तीन दिन पहले मृतक पर हमला किया था।

अपनी गवाही में, पीडब्ल्यू-4, जो मृतक का पड़ोसी था, ने कहा कि अभियुक्त पैसे और गहनों के लिए मृतक को परेशान करता था और मृतक की संपत्ति हड़पना चाहता था। गवाह द्वारा यह भी कहा गया है कि मृतक द्वारा परिसर खाली करने के लिए कहने के बावजूद अभियुक्त परिसर खाली नहीं कर रहा था और उस परिसर को हड़पना चाहता था जिसमें वह किराएदार था। गवाह ने आगे कहा कि 18.08.2013 को दोपहर 12 बजे वह नरेश चंद्र शुक्ला से बात कर रहा था, तभी उसने देखा कि अभियुक्त अपने दोस्तों के साथ मृतक को जबरन बोलेरो कार में ले जा रहा था और जब उन्होंने अभियुक्त का पीछा किया, तो अभियुक्त ने सरकारी अस्पताल में वाहन रोक दिया जहां डॉक्टर ने मृतक को मृत घोषित कर दिया। पीडब्ल्यू-5, जो मृतक की भाभी है, की गवाही भी अन्य गवाहों के समान ही है।

अभियोजन साक्षियों की गवाही के अवलोकन से पता चलेगा कि अभियोजन का मामला यह है कि अभियुक्त मृतक की संपत्ति हड़पना चाहता था और मृतक से पैसे और गहनों की मांग भी कर रहा था और जब मृतक ने अभियुक्त की मांगों को स्वीकार नहीं किया, तो अभियुक्त ने मृतक को जहर देकर मार डाला।

यह ध्यान देने योग्य है कि अभियुक्त द्वारा मृतक को जहर दिए जाने का अभियोजन का मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं बताया गया था, भले ही प्रथम सूचनाकर्ता ने पीडब्ल्यू-1 के रूप में अपनी गवाही में कहा था कि प्रथम सूचनाकर्ता के मामा पतिराम ने 18.08.2013 को ही प्रथम सूचनाकर्ता को यह खुलासा कर दिया था कि अभियुक्त ने मृतक को जहर दिया है।

इस स्तर पर, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर विचार करना प्रासंगिक होगा। रिपोर्ट मृतक के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं दर्शाती है। अपनी गवाही में, पीडब्ल्यू-6, यानी वह डॉक्टर जिसने शव का पोस्टमार्टम किया था, ने कहा है कि जबरन जहर देने के मामले में, व्यक्ति के होठों और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें हो सकती हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्पष्ट रूप से अभियोजन साक्षी के इस दावे की पुष्टि नहीं करती है कि अभियुक्त द्वारा मृतक के साथ मारपीट की गई थी और उसे जहर पीने के लिए मजबूर किया गया था। इस बात की प्रबल संभावना है कि अभियुक्त द्वारा मृतक को जबरन जहर दिए जाने के संबंध में अभियोजन साक्षियों की गवाही विचारण के दौरान तब ली गई जब विवेचकों को विसरा रिपोर्ट उपलब्ध हो गई थी, जिससे पता चला था कि मृतक ने जहर का सेवन किया था। परिस्थिति में, जहाँ तक अभियुक्त द्वारा मृतक को जबरन जहर दिए जाने का संबंध है, अभियोजन साक्षियों की गवाही 'सुधार' हो सकती है। पीडब्ल्यू-2 की गवाही कि वह इस तथ्य की चश्मदीद गवाह थी कि अभियुक्त मृतक को कुछ संदिग्ध पिला रहे थे, डीडब्ल्यू-1 की गवाही द्वारा खंडित होती है, जो मृतक की रिश्तेदार भी है और जो पीडब्ल्यू-2 के अनुसार, पीडब्ल्यू-2 के साथ थी जब वह मृतक से मिलने गई थी और वह भी तब उपस्थित थी जब अभियुक्त कथित तौर पर मृतक को कुछ तरल पीने के लिए मजबूर कर रहा था।

अपनी गवाही में, डीडब्ल्यू-1 ने इस बात से इनकार किया है कि वह पीडब्ल्यू-2 द्वारा वर्णित घटना की गवाह थी और उसने कहा है कि उपर्युक्त तथ्यों को बताते हुए शपथ पत्र पर उसके हस्ताक्षर गवाह को

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



शपथ पत्र पढ़कर सुनाए बिना प्राप्त किए गए थे। डीडब्ल्यू-1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष यह भी गवाही दी है कि अपना प्लॉट बेचने के बाद मृतक को प्राप्त राशि उसके बच्चों के बीच बांट दी गई थी। पीडब्ल्यू-2 के अलावा, अभियोजन का कोई अन्य गवाह इस तथ्य का चश्मदीद गवाह होने का दावा नहीं करता है कि अभियुक्त ने मृतक को कुछ ऐसा पीने के लिए मजबूर किया था जिसे पीडब्ल्यू-2 ने जहर होने का संदेह किया था। अभियोजन का यह दावा कि अभियुक्त ने मृतक को जहर पिलाया था, सुनी-सुनाई बात है, और अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन द्वारा पतिराम का परीक्षण नहीं किया गया है, भले ही अपनी गवाही में पीडब्ल्यू-1 दावा करता है कि पतिराम ने उसे बताया था कि अभियुक्त ने मृतक को जहर पीने के लिए मजबूर किया था।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के पठन से यह भी पता चलता है कि पीडब्ल्यू-1 और पीडब्ल्यू-3 की गवाही के बीच मुंबई में रहने के कारण के संबंध में बड़े अस्पष्टीकृत विरोधाभास हैं। अपनी गवाही में, पीडब्ल्यू-1 कहता है कि वह व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए मुंबई गया था, लेकिन पीडब्ल्यू-3, जो पीडब्ल्यू-1 की बहन है, कहती है कि वे पढ़ाई के लिए मुंबई गए थे। विचारण न्यायालय द्वारा पीडब्ल्यू-3 की गवाही पर इस आधार पर भरोसा नहीं किया गया है कि अपनी जिरह में, पीडब्ल्यू-3 उस कक्षा का खुलासा नहीं कर सकी जिसमें वह या उसका भाई, यानी पीडब्ल्यू-1 पढ़ रहे थे।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि पीडब्ल्यू-11, जो मामले के विवेचकों में से एक था, ने इस बात से इनकार किया है कि धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज उनके बयानों में किसी भी गवाह ने यह कहा था कि अभियुक्त ने मृतक को जहर पीने के लिए मजबूर किया था। गवाह ने यह भी कहा था कि पीडब्ल्यू-3 द्वारा विवेचक को दिए गए शपथ पत्र में यह नहीं कहा गया था कि अभियुक्त ने मृतक को जहर दिया था। गवाह ने इस बात से भी इनकार किया कि प्रथम सूचनाकर्ता ने विवेचक को बताया था कि अभियुक्त मृतक से गहनों और पैसों की मांग कर रहा था। यह तथ्य कि किसी भी अभियोजन साक्षी ने विवेचकों को सूचित नहीं किया था कि अभियुक्त ने मृतक को जहर दिया था, पीडब्ल्यू-8 द्वारा भी गवाही दी गई है, जिसने मामले की विवेचना भी की थी।

प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के 40 दिन बाद दर्ज की गई है, भले ही अभियोजन का मामला यह है कि प्रथम सूचनाकर्ता को अभियुक्त की भूमिका के बारे में फोन पर तब बताया गया था जब उसे 18.08.2013 को ही घटना के बारे में सूचित किया गया था और 19.08.2013 को उसके पड़ोसियों द्वारा। परिस्थितियों में, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में हुआ विलंब अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा करता है। इसी तरह, अपराध करने के लिए अभियुक्त पर आरोपित मकसद भी सिद्ध नहीं हुआ है। अभियोजन का यह दावा कि अभियुक्त ने मृतक को उसके स्वामित्व वाला एक प्लॉट बेचने के लिए विवश किया था और मृतक से पैसे और गहनों की मांग भी की थी, सिद्ध नहीं हुआ है। मृतक के स्वामित्व वाले गहनों का विवरण या मृतक के पास मौजूद राशि को भी अभियोजन द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि अपनी गवाही में, पीडब्ल्यू-1 ने कहा कि उसने अपनी मां के शरीर पर चोटें देखीं। गवाह द्वारा यह कहा गया है कि मृतक के कंधों पर चोटें थीं। हालांकि, गवाह के उक्त दावे की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से नहीं होती है जो खुलासा करती है कि मृतक के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अभियोजन साक्ष्य में उपरोक्त कमियों पर विचार करने के बाद, विचारण न्यायालय ने माना है कि अभियोजन अपने मामले को संदेह से परे सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा है और अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया है।

हमें विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के मूल्यांकन में कोई विषमता या कोई अन्य अवैधता नहीं मिली है। वर्तमान अपील में कानून या तथ्य का कोई प्रश्न या साक्ष्यों के मूल्यांकन के संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठता है जिससे हमें अपील स्वीकार करने और अपीलार्थी के आग्रह पर साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया जा सके। विचारण न्यायालय का निर्णय रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर आधारित है और विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक उचित दृष्टिकोण है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त सभी कारणों से, अपील को सरसरी तौर पर खारिज किया जाता है।

अपील को नियमित संख्या आवंटित करने के बाद और वर्तमान निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय को प्रमाणित करने के बाद फाइल को रिकॉर्ड में भेज दिया जाए।

(देवेन्द्र सिंह-I, न्यायमूर्ति) (सलिल कुमार राय, न्यायमूर्ति)

23 मार्च, 2026

विपाशा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"